



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 47]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2015

सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2015 के 2रे दिन पास्ति)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. पीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च 2011, जिसे 23 मई 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण पीपीटी के दरमान की वैधता कई बार विस्तारित कर चुका है (पिछला विस्तार आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा 31 दिसम्बर 2014 तक था।

3. पीपीटी ने संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 27 अगस्त 2012 को दाखिल किया था जिसे प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था और विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रस्ताव की आंतरिक रूप से संवीक्षा की जा रही है और इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

4.1. जब यह मामला इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए तैयार किया जा रहा है, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2013 द्वारा निवेदन किया था कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका था और वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिन पर विचार किया जाना है क्योंकि प्रहस्तित किए जाने के लिए अनुमानित कार्गो मिश्रण में बदलाव किया गया है और तेल कार्गो में पर्याप्त वृद्धि हुई

है। इसके अलावा, 12 अक्टूबर 2013 को भारी चक्रवात की वजह से, पत्तन ने अपनी संपत्तियों को हुए नुकसान उठाए थे जोकि लगभग रु. 82.71 करोड़ अनुमानित किया गया है। पीपीटी ने बताया है कि हुए नुकसानों की पूर्ति के लिए अनुदान प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार को किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है तो पीपीटी को यह सुधार लागत अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी करनी होगी जिसका इसके आंतरिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा।

4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए तीन महीने के समय की मांग की थी। पीपीटी द्वारा बताए गए कारणों से, पत्तन को उसके संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जनवरी 2014 तक का समय दिया गया था। चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी 2014 द्वारा उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने का अनुस्मरण करवाया गया था। पत्तन को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह देते हुए पीपीटी के साथ पत्राचार किया गया था। 30 सितम्बर 2014 तक मौजूदा दरमान की वैधता का विस्तार करते समय, पीपीटी को 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन उसका संशोधित प्रस्ताव 31 अगस्त 2014 तक दाखिल करने की दोबारा सलाह दी गई थी। पीपीटी से संशोधित प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। अतः, पीपीटी को लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई थी।

5. इसी बीच, पीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो चुकी है। यह स्वीकार करते हुए कि पीपीटी को उसका संशोधित प्रस्ताव अभी दाखिल करना है और पीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा, इसलिए यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च 2015 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014 (291)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2015

No. TAMP/62/2009-VPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/62/2009-VPT

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 2nd day of January, 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/61/2009-PPT dated 25th March, 2011 which was notified in the Gazette of India on 23rd May, 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31st March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on couple of occasions; the last extension being till 31st December, 2014 *vide* Order dated 30th September, 2014.

3. The PPT has filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August 2012 which was registered as tariff case and taken on consultation. The proposal has been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February 2013.

4.1 When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication dated 30 October 2013, submitted that the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the 2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around Rs. 82.71 crores. The PPT has stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2. In view of the above position, the PPT had sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR. For the reasons stated by PPT, the port was allowed time till 31 January 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February 2014. Correspondence were exchanged with PPT advising port to file its revised proposal. While extending the validity of the existing SOR till 30 September 2014, the PPT was again advised to file its revised proposal by 31 August 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005. The revised proposal from PPT is still awaited. The PPT is, therefore, advised to file its revised proposal following applicable tariff guidelines.

5. In the meantime, the extended validity of the existing SOR of PPT expired on 31 December 2014. Recognising that the PPT is yet to file its revised proposal and it will time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filled by the PPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 31 March, 2015 or till the effecting date of implementation of the revised Scale of Rates, Whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the PPT post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.- III/4/Exty./143/2014(291)]